श्री पदम देव : क्या मैं जान सकता हूं कि भूतपूर्व शासकों में बुशहर रियासत में जो सहूलियतें वहां के ताजिरों को दी हुई थीं, क्या वह अब भी दी जा रही हैं क्योंकि ऊन और पश्म का दारोमदार सारे का सारा तिब्बत पर निर्भर रहता है और तिब्बत की तिजारत काफ़ी खतरनाक है तो सरकार की ओर से पहले जो लोन मिलता था और सुरक्षा का प्रबन्ध होता था तो क्या यह दोनों सुविधाएं वर्तमान सरकार भी उनको दे रही है ?

श्री कानूनगो : यह तो आयात ही आयात का सवाल है । यहां जो थोड़ी सी दिक्कतें हैं वह तिब्बतन डालर्स मिलने को हैं और उस पर चीनी सरकार ने कुछ रुकावटें डाली हैं और जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको रूपी ड्राफ्ट हिन्दुस्तान में कैश करने में तकलीफ़ होती है । इस बारे में हम लोगों की चीन सरकार के साथ बातचीत हो रही है और उस पर ध्यान दिया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न के बारे में पिछले दो साल से चीन सरकार से बातचीत चल रही है और अब इस साल व्यापार का जो सीज़न है वह समाप्त होने वाला है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या खास अड़चनें पड़ रही हैं । जिनकी कि वजह से इतनी देरी हो रही है और कोई समझौता हमारे और उनके बीच में अभी तक क्यों नहीं हो सका है ?

श्री कानूनगो : बातचीत अभी हो रही है हम लोग उनको इजाज़त देने के लिए कह रहे हैं, अभी तक उनकी मंजूरी नहीं मिली है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि पिछले तीन या चार वर्षों से प्रतिवर्ष हमारे देश में तिब्बत से जो ऊन आती है उसका परिमाण घटता जा रहा है और क्या चीन सरकार के साथ बातचीत करने में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि वहां से पूरे परिमाण में हमारे यहां ऊन आती रहे ?

श्री कानूनगो : तिब्बत से हमारा व्यापार कम नहीं हुआ है वैसे ही चल रहा है और उसी के सम्बन्ध में हमारी बातचीत भी चल रही है ।

Shri Panigrahi: May I know whether the Indo-Tibetan trade is increasing or decreasing?

Shri Kanungo: Well, it is not increasing.

Information Centre

*1797. **Shri P. K. Deo:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the progress made in the proposal to set up an information Centre in Bhubaneshwar?

The Minister of Information and Broadcasting (Dr. Keskar): Arrangements are practically complete and the State Government are taking steps to open the Centre on 2nd October, 1957.

Lajpat Nagar Colony

*1799. **Shrimati Sucheta Kripalani:** Will the Minister of **Rehabilitation and Minority Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the land on which Lajpat Nagar Colony is built was a Nazul Land;

(b) whether it is a fact that the cost of development of this land is approximately Rs. 7 per sq. yard;

(c) whether it is a fact that the displaced persons are being charged at the rate of Rs. 15 to 20 per sq. yard for this land;

(d) whether it is the policy of Government to sell this land to the displaced persons' on no profit no loss basis i.e. charge them the actual cost of acquisition plus the cost of development; and

(e) if so, the reasons for charging higher rates from these displaced persons?

The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.